



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड—24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 मार्च, 2023 ई0 (फाल्गुन 27, 1944 शक सम्वत्) [संख्या—11

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	319—332	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	105—107	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	227—245	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 मार्च, 2023 ई०

संख्या 349/XXXI(1)/2023/पदो-01/2021-उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत सुश्री शैलजा सिंह को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल-10 (वेतनमान-₹56,100-177,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री शैलजा सिंह, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखा जाता है।

3- उक्त प्रोन्नति मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस०बी०)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4- उक्त पदोन्नति फलस्वरूप सुश्री शैलजा सिंह, अनुभाग अधिकारी को आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग में तैनात किया जाता है।

5- सुश्री शैलजा सिंह, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि०) अनुभाग-01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग-2

अधिसूचना

02 मार्च, 2023 ई०

संख्या 145/XX-2/2022-1(43)/2022-राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड जेल रिजर्व बंदीरक्षक तथा जेल बंदीरक्षक सेवा नियमावली, 2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड जेल रिजर्व बंदीरक्षक तथा जेल बंदीरक्षक सेवा (संशोधन)
नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जेल रिजर्व बंदीरक्षक तथा जेल बंदीरक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2. उत्तराखण्ड जेल रिजर्व बंदीरक्षक तथा जेल बंदीरक्षक सेवा नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्—

3(क)	स्तम्भ-1 विद्यमान नियम 'नियुक्ति प्राधिकारी' से 3(क) महानिरीक्षक, कारागार अभिप्रेत है;	स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम 'नियुक्ति प्राधिकारी' से गढ़वाल मण्डल की कारागारों हेतु वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार देहरादून तथा कुमाऊँ मण्डल की कारागारों हेतु वरिष्ठ अधीक्षक सम्पूर्णानन्द शिविर/केन्द्रीय कारागार सितारगंज, उधमसिंहनगर अभिप्रेत है;
------	--	--

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.145/XX-2/2022/-1(43)/2022 Dated March 02, 2023 for general information.

NOTIFICATION

March 02, 2023

No.145/XX-2/2022/-1(43)/2022--In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India the governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Jail Reserve Warders and Jail Warders Service Rules, 2011 (as amended from time to time):-

The Uttarakhand Jail Reserve Warders and Jail Warders Service (Amendment) Rules, 2023

Short title and Commencement	1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Jail Reserve Warders and Jail Warders Service (Amendment) Rules, 2023. (2) It shall come into force at once.
Amendment of rule 3	2. In the Uttarakhand Jail Reserve Warders and Jail Warders Service Rules, 2011, for the existing clause (a) of rule 3 set out in column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
3(a) "Appointing Authority" means the Inspector General of Prisons, Uttarakhand;	3(a) "Appointing Authority" means for the Jails of Garhwal division Senior Superintendent, District Jail, Dehradun and for the Jails of Kumaoun division Senior Superintendent, Sampurnanand Shivir/Central Jail Sitarganj, Udhamsingh Nagar;

अधिसूचना

02 मार्च, 2023 ई0

संख्या 146/XX-2/2022-1(43)/2022-राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड जेल महिला बंदीरक्षक सेवा नियमावली, 2011 (समय-समय पर यथासंशोधित) में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड जेल महिला बंदीरक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जेल महिला बंदीरक्षक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2023 है।						
	(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।						
नियम 3 का संशोधन	2. उत्तराखण्ड जेल महिला बंदीरक्षक सेवा नियमावली 2011 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 3 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्—						
	<table><tr><td>स्तम्भ-1</td><td>स्तम्भ-2</td></tr><tr><td>विद्यमान नियम</td><td>एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम</td></tr><tr><td>3(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से 3(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से गढ़वाल मण्डल की कारागारों हेतु वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार देहरादून तथा कुमाऊँ मण्डल की कारागारों हेतु वरिष्ठ अधीक्षक सम्पूर्णानन्द शिविर/केंद्रीय कारागार सितारगंज, उधमसिंहनगर अभिप्रेत है;</td><td></td></tr></table>	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2	विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम	3(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से 3(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से गढ़वाल मण्डल की कारागारों हेतु वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार देहरादून तथा कुमाऊँ मण्डल की कारागारों हेतु वरिष्ठ अधीक्षक सम्पूर्णानन्द शिविर/केंद्रीय कारागार सितारगंज, उधमसिंहनगर अभिप्रेत है;	
स्तम्भ-1	स्तम्भ-2						
विद्यमान नियम	एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम						
3(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से 3(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से गढ़वाल मण्डल की कारागारों हेतु वरिष्ठ अधीक्षक जिला कारागार देहरादून तथा कुमाऊँ मण्डल की कारागारों हेतु वरिष्ठ अधीक्षक सम्पूर्णानन्द शिविर/केंद्रीय कारागार सितारगंज, उधमसिंहनगर अभिप्रेत है;							

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.146/XX-2/2022/-1(43)/2022 Dated March 02, 2023 for general information.

NOTIFICATION

March 02, 2023

No.146/XX-2/2022-1(43)/2022-In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Female Jail Warders Service Rules. 2011 (as amended from time to time):-

The Uttarakhand Female Jail Warders Service (Amendment) Rules, 2023

Short title and Commencement	1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Female Jail Warders Service (Amendment) Rules, 2023.
	(2) It shall come into force at once.
Amendment of rule 3	2. In the Uttarakhand Female Jail Warders Service Rules, 2011, for the existing clause (a) of rule 3 set out in column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted, namely-

Column-1 Existing rule	Column-2 Rule hereby substituted
3(a) "Appointing Authority" means the Inspector General of Prisons, Uttarakhand;	3(a) "Appointing Authority" means for the Jails of Garhwal division Senior Superintendent, District Jail, Dehradun and for the Jails of Kumaoun division Senior Superintendent, Sampurnanand Shivir/Central Jail Sitarganj, Udham Singh Nagar;

अधिसूचनाप्रकीर्ण

02 मार्च, 2023 ई0

संख्या 147/XX-2/2023-1(33)/2013-राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड कारागार मुख्यालय लिपिक वर्गीय सेवा एवं उत्तराखण्ड कारागार (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा का एकीकरण किये जाने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तराखण्ड कारागार मुख्यालय लिपिक वर्गीय सेवा एवं उत्तराखण्ड कारागार (अधीनस्थ कार्यालय)

लिपिक वर्गीय सेवा का एकीकरण नियमावली, 2023

- | | |
|---------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड कारागार मुख्यालय लिपिक वर्गीय सेवा एवं उत्तराखण्ड कारागार (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा का एकीकरण नियमावली, 2023" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। |
| अध्यारोही प्रभाव | 2. किसी अन्य सेवा नियमावली या आदेश या संविलियन नियमावली में दी गयी किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी यह नियमावली प्रभावी होगी। |
| परिभाषाएं | 3. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :-
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(ख) "उपलब्ध रिक्ति" से ऐसी रिक्ति अभिप्रेत है, जो एकीकरण की तिथि को स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त हों;
(ग) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;
(घ) "मुख्यालय" से उत्तराखण्ड कारागार मुख्यालय अभिप्रेत है;
(ङ) "अधीनस्थ कार्यालयों" से उत्तराखण्ड कारागार मुख्यालय के नियन्त्रणाधीन केन्द्रीय कारागार/ सम्पूर्णानन्द शिविर/ जिला कारागार/ उप कारागार अभिप्रेत है;
(च) "भौतिक नियुक्ति" से सेवा के किसी संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों पर तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो। |
| एकीकरण | 4. (1) उत्तराखण्ड कारागार मुख्यालय लिपिक वर्गीय सेवा एवं उत्तराखण्ड कारागार (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा के कार्मिकों का, इस नियमावली के माध्यम से एकीकरण किया जाएगा।
(2) एकीकरण की तिथि से उत्तराखण्ड कारागार मुख्यालय लिपिक वर्गीय सेवा एवं उत्तराखण्ड कारागार (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा के समस्त कार्मिक "उत्तराखण्ड कारागार लिपिक वर्गीय सेवा" के कार्मिक कहलाएंगे। |

- एकीकरण के पश्चात् 5. एकीकरण के पश्चात् उत्तराखण्ड कारागार मुख्यालय लिपिक वर्गीय सेवा एवं उत्तराखण्ड कारागार (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा में स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए तदनुसार उत्तराखण्ड कारागार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार बनाई जायेगी।
- एकीकरण की प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश 6. एकीकरण के पश्चात् लिपिक वर्गीय कार्मिकों के पदस्थापन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी—
- (1) एकीकरण के पश्चात् लिपिक वर्गीय कार्मिकों की पदस्थापन/स्थानान्तरण मुख्यालय कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कहीं भी की जा सकेगी।
 - (2) एकीकरण के पश्चात् लिपिक वर्गीय कार्मिकों के सम्बन्ध में पृथक से "उत्तराखण्ड कारागार लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली" बनाई जाएगी।
 - (3) एकीकरण के पश्चात् लिपिक वर्गीय कार्मिकों के अर्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, भविष्य निर्वाह निधि, एन0पी0एस0, सेवा निवृत्तिक लाभ इत्यादि की गणना उनके द्वारा कारागार मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में की गयी राजकीय सेवा को सम्मिलित करते हुए, किया जाएगा।
- एकीकरण के पश्चात् 7. उत्तराखण्ड कारागार लिपिक वर्गीय सेवा के एकीकरण के कार्मिकों की ज्येष्ठता फलस्वरूप उत्तराखण्ड कारागार मुख्यालय लिपिक वर्गीय सेवा एवं कारागार (अधीनस्थ कार्यालय) लिपिक वर्गीय सेवा में मौलिक रूप से नियुक्ति कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 समय-समय पर यथा संशोधित के अधीन अवधारित की जाएंगी।
- निरसन एवं व्यावृत्ति 8. इस नियमावली के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप "उत्तराखण्ड कारागार विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 2017 निरसित की जाती है :
- परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली के अधीन कृत कार्यवाही मान्य होगी यदि वह इस नियमावली के उपबंधों से असंगत नहीं है।

परिशिष्ट--'1'

(नियम-5 देखें)

क्र० सं०	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स लेवल / वेतनमान	संख्या
1	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-10 रु० 56,100-1,77,500	01
2	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-8 रु० 47,600-1,51,100	02
3	प्रशासनिक अधिकारी	लेवल-7 रु० 44,900-1,42,400	03
4	प्रधान सहायक	लेवल-6 रु० 35,400-1,12,400	05
5	वरिष्ठ सहायक	लेवल-5 रु० 29,200-92,300	09
6	कनिष्ठ सहायक	लेवल-3 रु० 21,700-69,100	10
योग =			31

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.147/XX-2/2023/-1(33)/2013 Dated March 02, 2023 for general information.

NOTIFICATIONMiscellaneous

March 02, 2023

No.147/XX-2/2023/-1(33)/2013--In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to allow to make the following rules for the Integration of the Uttarakhand Jail Headquarters Ministerial Cadre Service and the Uttarakhand Jail (Subordinate Office) Ministerial Cadre Service, namely:-

The Integration of the Uttarakhand Jail Headquarters Ministerial Cadre Service and the Uttarakhand Jail (Subordinate Office) Ministerial Cadre Service Rules, 2023

- | | | |
|-------------------------------------|----|---|
| Short title and commencement | 1. | (1) These Rules may be called the Integration of the Uttarakhand Jail Headquarters Ministerial Cadre Service and the Uttarakhand Jail (Subordinate Office) Ministerial Cadre Service Rules, 2023. |
| Overriding effects | 2. | (2) It shall come into force at once. |
| Definitions | 3. | These Rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary there with in any other service rules or order or absorption rules. |
| | | In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:- |
| | | (a) 'Appointing Authority' means the Inspector General Jail Uttarakhand; |
| | | (b) 'Available vacancy' means such vacancy which is vacant against the sanctioned post on the date of integration; |
| | | (c) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand; |

(d) 'Headquarters' means Uttarakhand Jail headquarters.

(e) 'Subordinate Offices' means Central Jail under control of Uttarakhand Jail headquarters/ Sampurnanand Sivr/ District Jail/ Sub Jail ;

(f) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rule and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government.

Integration 4. (1) The integration shall be made through these rules of the employee of the Uttarakhand Jail Headquarters Ministerial Cadre Service and Uttarakhand Jail (Subordinate Office) Ministerial Cadre Service;

(2) The all employees of the Uttarakhand Jail Headquarters Ministerial Cadre Service and the Uttarakhand Jail (Subordinate Office) Ministerial Cadre Service shall be called the employees of the Uttarakhand Jail Ministerial Cadre services from the date of integration.

Ministerial Cadre Structure after the integration 5. After integration, including the sanctioned posts in the Uttarakhand Jail Headquarters Ministerial Cadre Service and the Uttarakhand Jail (Subordinate Office) Ministerial Cadre Service, the Uttarakhand Jail Ministerial Cadre Service Rules shall be made accordingly as per Appendix 1.

Procedure of integration and guidelines 6. The following procedure shall be followed for posting of Ministerial cadre employees after the integration-

(1) After the integration the posting/transfer of the Ministerial cadre employees may be made anywhere in the Directorate and Subordinate offices.

(2) After the integration regarding ministerial staff employees a separate the Uttarakhand ministerial cadre Rules shall be made.

(3) The calculation of earn leave, medical leave, GPF, NPS, retirement benefits etc. shall be made with including to the Government service be done in the Jail Headquarters and subordinate offices by him.

Seniority of the employees after integration 7.

The inter se seniority of the employees appointed as substantively in the state level cadre due to integration of the Uttarakhand Jail Headquarters Ministerial Cadre Service and the Uttarakhand Jail (Subordinate Office) Ministerial Cadre Service shall be determined according the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

Repeal
savings

and 8.

Due to commencement of these rules the Uttarakhand Jail Department Ministerial Cadre Service Rules, 2017 is repealed :

Provided that, notwithstanding such repeal anything done under the said rules shall be valid if it is not inconsistent with the provisions of these rules.

Appendix -1

(see rules 5)

S.I.	Name of post	Pay Matrix level/ pay scale	Number
1	Chief Administrative Officer	Level-10 Rs. 56,100- 1,77,500	01
2	Senior Administrative Officer	Level 8 Rs. 47,600- 1,51,100	02
3	Administrative Officer	Level 7 Rs. 44,900- 1,42,400	03
4	Head Assistant	Level 6 Rs. 35,400- 1,12,400	06
5	Senior Assistant	Level 5 Rs. 29,200- 92,300	09
6	Junior Assistant	Level 3 Rs. 21,700- 69,100	10
		Total	31

By Order,

RADHA RATURI,

Additional Chief Secretary.

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

अधिसूचना/पदोन्नति

23 फरवरी, 2023 ई0

संख्या 101733/XXVIII-1/ई0-45195/2023-एतद्वारा उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 सर्वर्ग के अन्तर्गत निदेशक के पद पर कार्यरत डा0 विनीता शाह को नियमित चयनोपरान्त, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के पद पर वेतन मैट्रिक्स रू0-182200-224100 लेवल-16 में पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डा0 आर0 राजेश कुमार,

सचिव।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

कार्यालय ज्ञाप

10 मार्च, 2023 ई0

संख्या 151/E-42355/VII-A-2/2023-महानिदेशक/आयुक्त उद्योग, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-3665/उ0नि0/2022-23, दिनांक 09.11.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तराखण्ड में विभिन्न इकाइयों द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी से ऑटोमेटिक वाहनों के रेडियल एवं बायस टायर्स एवं ट्यूब्स तथा टैक्स्टर्स टायर्स का विनिर्माण सतत् प्रक्रिया (Continuous Process) से किया जाता है। टायरों के निर्माण के लिए पॉलीमर्स, नेचुरल रबर, नायलॉन व पॉलिस्टर टायर कॉर्ड, स्टील वायर तथा अन्य कैमिकल्स का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में उपयोग किये जा रहे कच्चेमाल की मिक्सिंग, कलेण्डरिंग, एक्सट्रूजन टायर बिल्डिंग्स कर नाइट्रोजन तथा बॉयलर से भाप का प्रयोग कर Vulcanization in Curing Presses किया जाता है। उत्तराखण्ड में टायर विनिर्माण को सतत् प्रक्रिया उद्योग (Continuous Process Industries) के अधीन वर्गीकृत न किये जाने से इस उद्योग को सतत् प्रक्रिया उद्योग (Continuous Process Industries) के रूप में नियमित विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पाती है। जिससे उत्पाद विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान रोस्टिंग तथा पॉवर कट के कारण उनका उत्पादन कार्य प्रभावित होता है और विनिर्माण प्रक्रिया में उपयोग किया जा रहा कच्चा माल भी इससे खराब हो जाता है। तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में टायर विनिर्माणक इकाइयों को सतत् प्रक्रिया उद्योग (Continuous Process Industries) में अधिसूचित किया गया है।

अतएव, अब राज्यपाल उक्त प्रस्ताव के क्रम में शासन स्तर पर हुये सम्यक विचारोपरान्त राज्य में भी टायर विनिर्माण उद्योग को सतत् प्रक्रिया उद्योग (Continuous Process Industries) के रूप में चिन्हित किये जाने हेतु एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,

सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Office Memorandum No.151/E-42355/VII-A-2/2023/02(7)2022 Dated March 10, 2023 for general information.

Office Memorandum

March 10, 2023

No.151/E-42355/VII-A-2/2023/02(7)2022--It is hereby informed by the proposal letter No-3665/U.N./2022-23, dated 09.11.2022 from Director General/ Commissioner-Industries, Uttarakhand, that various units in Uttarakhand are manufacturing radial and bias, tires tubes and

tractors tires for automatic vehicles with modern technology. The manufacturing is done through continuous process. Polymers, natural rubber, nylon and polyester tire cord, steel wire and other chemicals are used for the manufacturing of tyres. Vulcanization in Curing Presses is done using nitrogen and steam boilers by mixing, calendering, extrusion tire buildings of the raw materials used in this process. Subject to non-classification of tire manufacturing under Continuous Process Industries in Uttarakhand, this industry does not get regular power supply in the form of Continuous Process Industries. Due to roasting and power cut during the process of product manufacturing, their production work is affected and the raw material used in the manufacturing process also gets spoiled due to this Tire manufacturing units in Tamil Nadu and Uttar Pradesh have also been notified as Continuous Process Industries.

Now, therefore, the Governor, in line of this said proposal, after due consideration at the government level, is pleased to approve the identification of the "tire manufacturing industry" as Continous Process Industry for the interest of the industrialisation in the state.

By Order,

DR. PANKAJ KUMAR PANDEY,

Secretary.

पंचायतीराज अनुभाग-2

विज्ञप्ति

06 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 399/XII(2)/2022-86(07)/2022-संयुक्त निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 357/855/जि०प०अ०को०/2021-22, दिनांक 26.07.2022 के माध्यम से प्रेषित अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चम्पावत के पत्र संख्या: 183/जि०प०/व्य०पत्रा०/2022-23, दिनांक 23.05.2022 एवं शपथ पत्र दिनांक 11.04.2022 तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका, भाग तीन के नियम-81-बी० के प्राविधानों के क्रम में श्री भगवत पाटनी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चम्पावत के सेवा अभिलेखों में अंकित स्थायी निवास का पता गृह जनपद चम्पावत के स्थान पर ग्राम-छेड़ा, पट्टी चण्डाक, विकास खण्ड-बिण, जनपद पिथौरागढ़ के आधार पर गृह जनपद पिथौरागढ़ में परिवर्तित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

ओमकार सिंह,

अपर सचिव।

पंचायती राज अनुभाग-1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

16 फरवरी, 2023 ई०

संख्या 166/XII(1)/23-86(34)2021-पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त श्री मनोज कुमार तिवारी को नियमित चयनोपरान्त उप निदेशक के रिक्त पद पर वेतनमान रु 67,700-2,08,700, वेतन मैट्रिक्स लेवल-11 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुये, पंचायती राज निदेशालय में सृजित उप निदेशक के पद पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कार्मिक को पदोन्नति के फलस्वरूप उप निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

आज्ञा से,

ओमकार सिंह,

अपर सचिव।

शहरी विकास अनुभाग-3

अधिसूचना

23 फरवरी, 2023 ई0

संख्या I/101728/IV(3)/2023-11(02 निर्वा0)/2022-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11'क' एवं 11'ख' की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पंचायत, थलीसैण, जनपद पौड़ी के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं।

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पंचायत क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ-01 से 04 में उल्लिखित किया गया है।

नगर पंचायत थलीसैण, जिला-पौड़ी गढ़वाल

क्र0 सं0	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा	वार्ड से सम्बन्धित मोहल्लों का नाम
1	कैन्चूर-1 रणाखोल -ढाकोट	पूरब-ग्राम रौली की सीमा पश्चिम-वन विश्राम भवन (थलीसैण) उत्तर-ग्राम जल्लू की सरहदी रौली दक्षिण-ग्राम रौली की सरहद	वार्ड न0-1 में सम्मिलित मोहल्ले- रणाखोल, ढाकोट,कोंकाल, भुजेटी झिंडोली लामसेन बजवाड़, फुटाणी, थोरा
2	कैन्चूर-2 विचलाखोल पंज्याणाखोल, मैरुवा	पूरब-कच्चा मोटर मार्ग (कैन्चूर-रौली) पश्चिम-ग्राम ऐंठी की सरहद उत्तर-कैन्चूर बैण्ड (एन0 एच0 309) दक्षिण- ग्राम रौली की सरहद	वार्ड न02 में सम्मिलित मोहल्ले- विचलाखोल पज्याणाखोल, किरपाणी खोल बूमबगड, मैरुवा
3	अपर थलीसैण बाजार लगा कैन्चूर अनुसूचित जाति बस्ती	पूरब-कच्चा मोटर मार्ग (कैन्चूर-रौली) पश्चिम-बाजार सड़क थलीसैण उत्तर-वन विभाग भूमि/ राशन गोदाम दक्षिण-विचलाखोल/ पज्याणाखोल की सीमा	वार्ड न03 में सम्मिलित मोहल्ले- थलीसैण मुख्य बाजार सड़क से ऊपर की ओर की आबादी एवं कैन्चूर अनुसूचित जाति बस्ती मोहल्ला
4	लोअर थलीसैण बाजार लगा रण्डोला	पूरब-थलीसैण बाजार सड़क-जखोला मार्ग पश्चिम-वन विभाग (जंगलात) उत्तर- बस अड्डा थलीसैण सड़क एन0एच0 309 दक्षिण- वूमबगड तोक	वार्ड न0 4 सम्मिलित मोहल्ले- थलीसैण मुख्य बाजार सड़क के नीचे की ओर की आबादी व ग्राम रण्डोला मोहल्ला

अधिसूचना

23 फरवरी, 2023 ई०

संख्या I/101729/IV(3)/2023-11(02 निर्वा०)/2022-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11'क' एवं 11'ख' की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पंचायत, तपोवन, जनपद-टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं:-

(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पंचायत क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 4 में उल्लिखित किया गया है।

नगर पंचायत तपोवन, जनपद- टिहरी गढ़वाल

कक्ष संख्या	कक्ष का नाम	वार्ड का नाम	वार्ड से सम्बन्धित मौहल्ले के नाम
वार्ड सं०-01	उपला तपोवन	उ०-सीमा वार्ड सं०-4 द०-सीमा वार्ड सं०-3 पू०-सीमा वार्ड सं०-2 प०-सीमा वार्ड सं०-4	डिकॉन वैली, बाबा बालकनाथ मंदिर, बालकनाथ मार्ग
वार्ड सं०-02	मध्य तपोवन	उ०-सीमा मुनिकीरेती द०-सीमा वार्ड सं०-3 पू०-सीमा वार्ड सं०-3 प०-सीमा वार्ड सं०-1	बालकनाथ मार्ग, गुलाब नगर, इण्टर कालेज, स्वीस कॉटेज (विरखेत)
वार्ड सं०-03	निचला तपोवन	उ०-सीमा मुनिकीरेती द०-गंगा नदी पू०-गंगा नदी प०-सीमा वार्ड सं०-2	लक्ष्मण झूला पुल, लक्ष्मण झूला पैदल मार्ग, गौ-घाट, साईं घाट, लक्ष्मण चौक
वार्ड सं०-04	घुघत्याणी	उ०-सीमा वन क्षेत्र द०-सीमा वन क्षेत्र पू०-सीमा वार्ड सं०-1 प०- सीमा वन क्षेत्र	होटल अलोहा, राम मंदिर, सौरियाला मंदिर, उपला तपोवन

आज्ञा से,
नवनीत पाण्डे,
अपर सचिव।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-2

अधिसूचना

24 फरवरी, 2023 ई0

संख्या 150/XXXii(2)/2023-02(छः)/2013—श्री विरेन्द्र प्रसाद, अथवा विरेन्द्र भट्ट, वाहन चालक राज्य सम्पत्ति विभाग के सेवा अभिलेखों में उनका नाम अलग-अलग दर्ज होने के कारण श्री भट्ट द्वारा किये गये नाम परिवर्तन के अनुरोध पर सम्यक विचारोपरांत, उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड में यथावत लागू) शासनादेश संख्या-3497/III-500(5)-46 दिनांक 6 नवम्बर, 1946 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत श्री भट्ट, वाहन चालक राज्य सम्पत्ति विभाग के सेवा अभिलेखों में उनका नाम श्री विरेन्द्र प्रसाद, अथवा विरेन्द्र भट्ट के स्थान पर श्री बीरेन्द्र दत्त भट्ट, किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

सुरेन्द्र सिंह रावत,

संयुक्त सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 मार्च, 2023 ई० (फाल्गुन 27, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

December 08, 2022

No. 1434/III-A-07/2022/SLSA--Ms.Shama Parveen, Secretary, District Legal Services Authority, Nainital is hereby sanctioned medical leave for a period of 23 days w.e.f. 12.11.2022 to 04.12.2022.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

R.K. KHULBEY

Member Secretary,

Uttarakhand State Legal Services

Authority, Nainital.

**UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY,
HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL**

NOTIFICATION

February 21, 2023

No. 222/III-B-2009-10/SLSA/2019--In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987, provisions of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 and pursuant to the recommendation of the Hon'ble High Court of Uttarakhand vide Letter No. 710/UHC/XIII/f-1/Admin.A/2018, dated 20th February, 2023, **Sri Sudhir Kumar Singh, 8th Additional District & Sessions Judge, Dehradun** is hereby given the additional charge of the office of Chairman, Permanent Lok Adalat, Dehradun. This order will come into force with immediate effect.

By Order of the Patron-in-Chief,

Sd/-

R.K. KHULBEY

Member Secretary.

कार्यालय डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

28 फरवरी, 2023 ई०

पत्रांक 435/IV-12(2021)-डॉ० आर० एस० टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा में पुलिस विभाग उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा-2016 (पुलिस उपाधीक्षक) हेतु दिनांक 13-15 फरवरी, 2023 की अवधि में विभागीय परीक्षा आयोजित की गयी थी।

विभागीय परीक्षा (उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा-2016 (पुलिस उपाधीक्षक)) 2022-2023 में सम्मिलित निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है :-

अनुक्रमांक	परीक्षार्थी का नाम सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	तैनाती कार्यालय/रा०औ० प्रशि० सं० का नाम	प्रश्न-पत्रों का विवरण				
			क	ख	ग	घ	ङ
P-2023-01	अभिनय चौधरी	नैनीताल	अह	अह	अह	अह	अह
P-2023-02	अंकित कण्डारी	बागेश्वर	अह	अह	अह	अह	अह
P-2023-03	अस्मिता ममगाई	टिहरी	अह	अह	अह	अह	अह
P-2023-04	हर्षवर्धनी सुमन	रुद्रप्रयाग	अह	अह	अह	अह	अह
P-2023-05	नताशा सिंह	चमोली	अह	अह	अह	अह	अह
P-2023-06	नीरज सेमवाल	देहरादून	अह	अह	अह	अह	अह
P-2023-07	निहारिका सेमवाल	हरिद्वार	अह	अह	अह	अह	अह
P-2023-08	नितिन लोहनी	नैनीताल	अह	अह	अह	अह	अह

P-2023-09	ओशिन जोशी	अल्मोड़ा	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह
P-2023-10	परवेज अली	पिथौरागढ़	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह
P-2023-11	प्रशान्त कुमार	उत्तरकाशी	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह
P-2023-12	सुमित पाण्डे	एसटीएफ	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह
P-2023-13	स्वप्निल मुयाल	अभि0 मुख्यालय	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह
P-2023-14	विमा दीक्षित	नैनीताल	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह
P-2023-15	वैभव सैनी	पौड़ी गढ़वाल	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह
P-2023-16	विमल रावत	रूद्रप्रयाग	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह
P-2023-17	विवेक सिंह कुटियाल	चम्पावत	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह	अर्ह

विषय :

- 'क' Criminal procedure Code
 'ख' Indian penal Code and Indian Evidence Act
 'ग' Special Acts
 'घ' Police Regulation
 'ङ' Financial and Account Rules
 'च' Hindi (Translation)
 'छ' Hindi (Reading)

प्रकाश चन्द्र,

संयुक्त निदेशक (प्र0)

उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून

कार्यालय ज्ञाप 08

02 फरवरी, 2023 ई0

संख्या 26/उ0लो0से0अधि0/देहरादून-श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून को शासनादेश संख्या : 54-एक(1)/XXXVI(1)/2006-6-एक (2)/06, न्याय अनुभाग-1, देहरादून दिनांक 25 अगस्त, 2006 के अनुसार दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2024 तक की एक ब्लॉक अवधि हेतु एक माह दिनांक 01.12.2022 से दिनांक 30.12.2022 की अवधि का अर्जित अवकाश नकदीकरण स्वीकृत किया गया है।

मा0 अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से

सियाराम वर्मा,

उप-निबन्धक

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 हिन्दी गजट/82-भाग 1-क 2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 18 मार्च, 2023 ई0 (फाल्गुन 27, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे पिता स्वर्गीय लोक बहादुर थापा के सैन्य अभिलेख सैनिक नं0 5735233 X HAV मे मेरा नाम त्रुटिवश मंजू देवी दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम मंजू राधा है। भविष्य में मुझे मंजू राधा पुत्री स्वर्गीय लोक बहादुर थापा के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मंजू राधा पुत्री स्वर्गीय लोक बहादुर थापा

निवासी 85 निग गलैक्सी पब्लिक स्कूल

गजियावाला देहरादून उत्तराखण्ड।

कार्यालय नगर पंचायत पीपलकोटी, चमोली

सार्वजनिक सूचना

30 जनवरी, 2023 ई0

संख्या 429/सम्पत्ति कर/2022-23-नगर पंचायत पीपलकोटी चमोली की सीमांतर्गत उ0प्र0नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) की धारा-298(1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 के अंतर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर भवन/संपत्ति कर आरोपित करने के उद्देश्य से नगर पंचायत पीपलकोटी द्वारा "संपत्ति/भवन उपविधि-2022" बनाई गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301(1) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत पीपलकोटी चमोली को प्रेषित की जा सकेगी, वाद प्राप्त अप्पत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

यह उपविधि शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

संपत्ति/भवनकर उपविधि - 2022

1- संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ:-

- (क) यह उपविधि नगर पंचायत पीपलकोटी "संपत्ति/भवन उपविधि-2022" कहलाएगी।
- (ख) यह उपविधि नगर पंचायत पीपलकोटी की सीमा में प्रावृत्त होगी।
- (ग) यह उपविधि नगर पंचायत पीपलकोटी द्वारा प्रख्यापित तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रावृत्त होगी।

2- परिभाषाएँ

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

- (क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत पीपलकोटी से है।
- (ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत पीपलकोटी की सीमा से है।
- (ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पीपलकोटी से है।
- (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत पीपलकोटी के निर्वाचित अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- (ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत पीपलकोटी के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्य अथवा प्रशासक से है।
- (च) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका-1916 (उत्तराखंड में यथा प्रावृत्त) से है।
- (छ) "वार्षिक मूल्यांकन" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-140 व धारा-141 के अंतर्गत वार्षिक मूल्य से है।
- (ज) "संपत्ति/भवनकर" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 के अंतर्गत भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर से है।
- (झ) "समिति" का तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-104 के अंतर्गत गठित समिति से है।
- (ञ) "भवन एवं भूमि" का तात्पर्य नगर पंचायत सीमांतर्गत निर्मित भवन एवं भूमि से है।
- (ट) "स्वामी" का तात्पर्य भवन एवं भूमि के स्वामी से है।
- (ठ) "अध्यासी" का तात्पर्य नगर पंचायत सीमांतर्गत निर्मित भवन एवं भूमि पर किराए में रहने वाले व्यक्तियों से है।

3- वार्षिक मूल्यांकन- नगर पंचायत सीमांतर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन सीमांतर्गत स्थित भूमि एवं निर्मित भवन पर संपत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम -1916 की धारा-141 (2) के अंतर्गत कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर परिश्रमिक सहित या रहित किसी व्यक्ति या

व्यक्तियों को चाहे वे सदस्य हों, या न हो अथवा संस्था/एजेंसी नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति/संस्था/एजेंसी ऐसे प्रयोजन के लिए किसी सम्बद्ध संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं। संपत्ति/भवनकर निर्धारण हेतु निम्नानुसार वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा।

- (क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनवासीय भवनों की दशा में भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत लो0नि0वि0 के प्रचलित सेड्यूल रेट और उससे अनुलग्न भूमि की अनुमानित मूल्य तत्समय प्रचलित सर्किल रेट को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अनाधिक पर वार्षिक मूल्यांकन का आंकलन किया जाएगा।

- (ख) खंड (क) के उपबंधों के अंतर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथा स्थिति भवन की दशा में प्रतिवर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर या भूमि की दशा में प्रतिवर्ग फुट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किए जाने पर आए 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिये प्रतिवर्ग फुट मासिक किराया दर पर इस प्रकार होगी जैसे कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टांप अधिनियम -1899 के प्रयोजन के लिए कलैक्टर द्वारा नियम सर्किल दर के आधार पर नियत किया गया जाए और ऐसे भवन या भूमि के लिए क्षेत्रफल में चालू न्यूनतम दर और अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे निहित किए जायें।

- (ग) खण्ड (क) (ख) के अंतर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में यथास्थिति, ऐसे आवासीय एवं अनवासीय (दुकानात) जो किराए पर उठाए गए हों, उनका वार्षिक मूल्यांकन शहर की प्रचलित बाज़ार दर अथवा उस क्षेत्र के लिए कलैक्टर द्वारा तत्समय किराए हेतु प्रचलित सर्किल रेट से जो भी अधिकतम हों, के अनुसार किराए के भवन के प्रतिवर्ग फिट या मीटर मासिक किराया दर पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराए को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण करना होगा और मासिक किराए को 12 गुना पर वार्षिक मूल्यांकन पर निर्धारण हेतु किया जाएगा।

प्रतिबंध यह है कि जहां नगर पंचायत की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपर्युक्त विधि से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो, वहाँ नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जो उसे समयपूर्ण प्रतीत हों वार्षिक मूल्य नियत कर सकती हैं।

- 1- वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए कारपेट क्षेत्र की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी-
 - (i) कक्ष- आंतरिक आयाम की पूर्ण माप,
 - (ii) आद्यादित बरामदा- आंतरिक आयाम की पूर्ण माप,
 - (iii) बलकोनी, गलियारा, रसोई घर और भंडार गृह- आंतरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,
 - (iv) गैराज-आंतरिक आयाम की एक चौथाई माप,
 - (v) स्नानागार, शौचालय, द्वारमंडप और जीना से आद्यादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।
- 2- उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम-1972 के प्रयोजन के लिए किसी भवन का मानक किराया, या युक्तियुक्त वार्षिक किराए को भवन के वार्षिक गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जाएगा।
- 3- संपत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु वार्षिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक भवन एवं भूमि का मौके पर निरीक्षण करने के उपरांत यथास्थिति के अनुसार किया जाएगा।
- 4- भूमि/भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर कर- भवन एवं भूमि के वार्षिक मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत संपत्ति/भवन कर लिया जाएगा, परंतु निम्नलिखित भवन एवं भूमि अथवा उसके भाग निम्नानुसार कर से मुक्त रहेंगे।
 - (क) मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद अथवा दूसरे धार्मिक संस्थाएं जो सार्वजनिक तथा रजिस्टर्ड ट्रस्ट या संस्था के अधीन हो, परंतु जो स्थान अथवा स्थानों के भाग रहने अथवा किराए पर या अन्य प्रकार से आय अर्जित की जाती है तो उन पर कर की छूट का नियम लागू नहीं होंगे।
 - (ख) अनाथालय, स्कूल, छात्रावास, चिकित्सालय, धर्मशालाएँ, तथा इस प्रकार से अन्य भवन तथा भूमि जो इस प्रकार की दान की संस्थाओं की परिसंपत्तियाँ और उन्ही संस्था द्वारा ऐसे कार्य करती हों।
 - (गं) नगर पंचायत पीपलकोटी की समस्त संपत्तियाँ।

- 5- कर निर्धारण सूचियों का प्रकाशन- भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर संपत्ति/भवन कर निर्धारण हेतु नगरपालिका अधिनियम- 1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गयी सूचीयों का प्रकाशन जनसामान्य के अवलोकनार्थ एवं निरीक्षण के लिए नगर पंचायत कार्यालय में अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदर्शित की जाएगी तथा समाचार पत्र में इस आशय की सूचना प्रकाशित करते हुए अपील होगी कि पंचवर्षीय गृह कर का निर्धारण किया जा चुका है, जिस किसी व्यक्ति अथवा स्वामी या अध्यासी को कर निर्धारण सूची का अवलोकन एवं निरीक्षण करना हो वे नगर पंचायत कार्यालय में आकर कर निर्धारण सूचियों का अवलोकन एवं निरीक्षण कर सकते हैं, तथा प्रस्तावित कर निर्धारण की सूचना संबन्धित प्रत्येक भवन स्वामी को 15 दिन के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दी जानी आवश्यक होगी और कर निर्धारण सूचियों में प्राप्त आपत्तियों को मोहल्ले/वार्ड वार क्रम सं0 देते हुए आपत्ति एवं निस्तारण पंजिका में अंकित किया जाएगा।
- 6- आपत्तियों का निस्तारण- भूमि एवं भवन के वार्षिक मूल्यांकन अथवा कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु नगर पालिका अधिनियम- 1916 की धारा -104 के अंतर्गत गठित समिति अथवा समिति गठित न होने के फलस्वरूप अधिशासी अधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से किया जाएगा।
- प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई हेतु तिथि एवं समय नियत करते हुये आपत्तिकर्ता को लिखित सूचना प्रेषित करनी होगी,
 - आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति एवं निर्णय संबन्धित पत्रावली अथवा आपत्ति निस्तारण पंजिका में जस्टीफिकेशन के साथ दर्ज करनी होगी,
 - शासनादेश सं0 2054/नौ-9-97-79ज/97 दिनांक 28.06.1997 द्वारा वार्षिक मूल्यांकन एवं कर निर्धारण पर प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण दिये गए निर्देशानुसार की जाएगी।
- 7- कर निर्धारण सूचियों का अभिप्रमाणीकरण और अभिरक्षा- (क) अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित करेगा।
- इस प्रकार से अभिप्रमाणित सूची को नगर पंचायत कार्यालय में जमा की जाएगी,
 - जैसे ही सम्पूर्ण नगर क्षेत्र की सूची इस प्रकार से जमा कर दी जाए वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा घोषणा की जाएगी,
 - कर निर्धारण सूचियों में उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण कार्यवाही होने के उपरांत संपत्ति/भवन कर मांग एवं वसूली पंजिका में अंतिम रूप से सूची दर्ज करते हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-166 के अंतर्गत दावों की वसूली हेतु अग्रेत्सर कार्यवाही शासन द्वारा समय-समय पर दिये गए निर्देशानुसार करनी होगी।
- 8- कोई भी व्यक्ति किसी समय भवनों की एसेसमेंट सूची पर अपना बतौर स्वामी दर्ज करा सकता है और जिस समय तक आवेदन-पत्र को अस्वीकार करने का काफी कारण न हो उसका नाम दर्ज कर लिया जाएगा अस्वीकृति का कारण लिख दिया जाएगा।
- 9- जब इस बात में शक हो कि भवन या भूमि पर कि जिसका नाम स्वामी के रूप में दर्ज किया जाए तो बोर्ड या समिति या वह अधिकारी जिसकी बोर्ड ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम -1916 की धारा 143 (3) के अधीन अधिकार दिया हो, यह तय करेगा कि किसका नाम स्वामी के तौर पर दर्ज होना चाहिए। इसका निश्चय उस समय तक लागू रहेगा जब तक सशक्त न्यायालय उसको रद्द न कर दे।
- 10- (1) अगर किसी ऐसे भवन या भूमि के स्वामी होने का अधिकार जिस पर यह कर लागू हो, हस्तांतरित किया जावे तो अधिकार हस्तांतरित करने वाला या जिसको हस्तांतरित किया जावे, वह यदि कोई दस्तावेज़ न लिखी गयी हो तो अधिकार लेने की तिथि से और लिखी गयी हो तो दस्तावेज़ लिखे जाने या रजिस्ट्री होने या हस्तांतरित होने की तिथि से तीन माह के अंदर हस्तांतरित होने की सूचना अध्यक्ष को अथवा अधिशासी अधिकारी को देगा।
- (2) किसी ऐसे भवन या भूमि का स्वामी जिस पर कर लागू है, की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी या जो जायदाद का स्वामी हो, इसी प्रकार स्वामी होने से तीन माह के अंदर सूचना देगा।
- 11- (1) सूचना में जिसका विवरण पहले दिया गया है, उक्त नियम में उल्लिखित सभी विवरण सफाई से और ठीक तौर से दिये जाएंगे।

(2) हर ऐसा व्यक्ति जिसको जायदाद हस्तांतरित की गयी हो, अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दस्तावेज़ (अगर लिखी गयी हो) या उसकी एक प्रतिलिपि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1877 ई0 के अनुसार ली गयी हो, पेश करेगा।

- 12- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम- 1916 की धारा- 151 (2) के अधीन कर की थोड़ी माफी या ऐसी माफी के लिए भवन का स्वामी जिसमें कई किरायेदार रहते हो, भवन पर कर लागू करने के समय बोर्ड से प्रार्थना कर सकता है कि तमाम भवन का कर लागू करने के अलावा हर एक भाग का वार्षिक मूल्य अलग-अलग एक नोट में दर्ज किया जावे और जब कोई भाग, जिसका वार्षिक मूल्य अलग दर्ज हो गया है, या किराए के नब्बे (90) दिन या इससे अधिक समय के लिए किसी साल में खाली रहा हो तो कुल भवन के कर का वह हिस्सा माफ किया जावे जो कि उक्त एक्ट की धारा 151 (1) के अधीन वापस या माफ किया जाता यदि भवन के भाग पर अलग कर लागू किया होता।

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा- 299 (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके नगर पंचायत एतद्वारा निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि उल्लंघन करने के लिए अर्थदण्ड रु0 1,000.00 (एक हजार) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरंतर जारी रहा हो तो प्रथम दोषसिद्धी के दिनांक से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाए कि अपराधी अपराध करता रहा है, अतिरिक्त जुर्माना किया जा सकता है, जो रु0 1,00.00 (एक सौ) प्रतिदिन तक हो सकता है।

बीना नेगी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत पीपलकोटी।

रमेश लाल बड़वाल,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत पीपलकोटी।

कार्यालय नगर पंचायत लालकुआँ जिला-नैनीताल

सार्वजनिक सूचना

नगर पंचायत लालकुआँ ट्रेड लाइसेंस उपविधि

12 सितम्बर, 2022 ई0

पत्रांक 299/न0प0/लाई0ग0/उप0/प्रका0/2022-23-उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 298 (2) की सूची-01 के अन्तर्गत नगर पंचायत लालकुआँ की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर लाइसेंस/पंजीकरण शुल्क दरें निर्धारित की जानी हैं। अतः नगर पंचायत लालकुआँ के अधिसूचना क्षेत्र की परिधि में आने वाली सामान्य जनता या फिर जिस पर इस अधिरोपित कर का प्रभाव पड़ने वाला है उनसे आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। लिखित आपत्ति एवं सुझाव इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लालकुआँ को सम्बोधित करते हुये नगर पंचायत लालकुआँ कार्यालय में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक उपलब्ध कराये जा सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिभाषा-

1. यह उपविधि नगर पंचायत लालकुआँ की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों का नियन्त्रण करने हेतु लाइसेंसिंग एवं अन्य शुल्क उपविधि वर्ष 2022-23 कहलायेगी, जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
(क) अधिनियम-अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) से है।
(ख) नगर पंचायत लालकुआँ सीमा से तात्पर्य- नगर पंचायत लालकुआँ की सीमा शासन द्वारा निर्धारित है।
(ग) अधिशासी अधिकारी-अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत लालकुआँ के अधिशासी अधिकारी से है।
(घ) अध्यक्ष-अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत लालकुआँ के निर्वाचित अध्यक्ष से है।
(ङ) बोर्ड- बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत लालकुआँ के बोर्ड से है।
(च) लाइसेंसिंग अधिकारी-लाइसेंसिंग अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत लालकुआँ के अधिशासी अधिकारी से है।
2. नगर पंचायत लालकुआँ की सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करने का पात्र तभी होगा, जब वह इस हेतु नगर पंचायत लालकुआँ में निर्धारित शुल्क का भुगतान का लाइसेंस प्राप्त कर ले।
3. इस उप नियम के अन्तर्गत लाइसेंस की अवधि प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च (वित्तीय वर्ष) के लिये वैध होगी।
4. प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी के लिये इन उपविधियों के अधीन नगर पंचायत लालकुआँ कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रतिवर्ष फरवरी मॉह के प्रथम सप्ताह से 31 जुलाई तक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. लाइसेंस अधिकारी लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक दुकान/प्रतिष्ठान/हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/एजेन्सी/कम्पनी/प्रशिक्षण केन्द्र आदि के निरीक्षण करने का अधिकारी होगा अथवा लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी से जाँच कराने पर लाइसेंस निर्गत करेगा।
6. लाइसेंस अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान-पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल, दुकान हलवाई, सब्जी विक्रेताओं आदि की दुकानों के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली गन्दगी के विरुद्ध अथवा सड़ी गली फल सब्जियों को रखने व विक्रय करने के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकारी होगा।
7. प्रत्येक व्यापारी को चाहिये कि वह नगर पंचायत लालकुआँ कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त करने हेतु फरवरी मॉह के प्रथम सप्ताह से 31 जुलाई तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त करेगा।
8. इस उपविधि के अधीन खान-पान से सम्बन्धित व्यवसायों/दुकानों के अलग-बगल व सामने प्रवेश द्वार के समक्ष दुकान का कूड़ा व ऐसी अनुपयुक्त गन्दी वस्तुयें रखने, प्रदर्शित करने व फेंकने का अधिकार नहीं होगा जो सामाजिक दृष्टि से हानिकारक या जनस्वास्थ्य के विपरीत हो इसके उल्लंघन पर उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 तथा अन्य नियमों, उपविधियों तथा मा0 उच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) के अनुसार दण्डात्मक कार्यावाही की जायेगी।
9. लाइसेंस धारक यदि अपने लाइसेंस का नवीनीकरण फरवरी मॉह के प्रथम सप्ताह से 31 जुलाई तक नहीं कराता है तो विलम्ब शुल्क/अर्थदण्ड हेतु निर्धारित लाइसेंस शुल्क 10 प्रतिशत प्रति मॉह की दर से लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा, एवं अधिकतम विलम्ब शुल्क/अर्थदण्ड कुल लाइसेंस शुल्क का दो गुना होगा, जिसकी वसूली भू-राजस्व की भाँती की जा सकेगी। विलम्ब शुल्क हेतु दिनांक की गणना 01 अप्रैल से की जायेगी।
10. कोई व्यक्ति/लाइसेंस धारक अपना व्यवसाय समाप्त करेगा तो अपना लाइसेंस निरस्त करने हेतु रुपया 10.00 के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थना पत्र मार्च माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा जिसमें लाइसेंस अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराकर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

11. इस उपविधि के किसी प्रावधान के बारे में राज्य सरकार यदि सन्तुष्ट है, कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, अथवा कोई प्रावधान जनहित में नहीं है, तो उक्त प्रावधान को परिष्कृत करने/छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
12. नगर पंचायत सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को व्यवसाय नहीं करेगा, जिस पर राज्य सरकार/शासन द्वारा पूर्ण निषेध किया जा चुका है।
13. केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा नगर पंचायत लालकुओं में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाईसेंस इन उपविधियों से भिन्न होंगे।
14. नगर पंचायत लालकुओं की सीमान्तर्गत लगने वाले मेले में अस्थाई व्यवसाय की दरें जो व्यवसाय सूची में नहीं हैं उनकी लाईसेंस की दरें नगर पंचायत लालकुओं अधिशासी अधिकारी द्वारा तय की जा सकेंगी।
15. नर्सिंग होम, हॉस्पिटल, क्लीनिक आदि से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण (ट्रीटमेंट) अनिवार्य रूप से बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु अधिकृत व्यक्ति/संस्था/कम्पनी द्वारा करवाना होगा। खुले में या टैंचिंग ग्राउण्ड में उक्त वेस्ट फेंकने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यावाही की जायेगी।
16. बैंकट हॉल/होटल को स्वच्छता के सम्बन्ध में समय-समय पर नगर पंचायत लालकुओं के द्वारा बनाये गये नियमों/उपनियमों एस0डब्ल्यू0एम0 नियम 2016 तथा मा0 उच्च न्यायालय/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) के आदेशों को पालन प्रत्येक दशा में करना होगा।
17. नगर पंचायत लालकुओं के अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को किसी भी समय व्यवसाय/दुकान आदि के लाईसेंस का परीक्षण करने का अधिकार होगा।
18. नगर पंचायत लालकुओं द्वारा जारी किये गये कुछ लाईसेंस में यदि भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य द्वारा रजिस्ट्रेशन/लाईसेंस निर्मित होता हो तो उक्त प्रमाण प्रस्तुत करने के उपरान्त नगर पंचायत लालकुओं द्वारा रजिस्ट्रेशन/लाईसेंस जारी किये जायेंगे।
19. ट्रांसपोर्टर्स/मोटर वाहन सेल्स एवं सर्विस आदि फुटपाथ/सड़क पर कोई वाहन खड़ा/सर्विस आदि नहीं करेगा।
20. पेट्रोल/डीजल आर्येल कम्पनी द्वारा वितरण स्थल पर वाहन को तेल भराने हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था एवं शौचालय/पानी आदि की व्यवस्था भी करनी होगी।
21. धुलाई/लान्डी, हेतु पानी की निकासी प्राविधानिक तरीके से अपनायी जाये।
22. प्रत्येक व्यवसायी/लाईसेंस धारक को स्वच्छ भारत मिशन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद यथा पॉलीथीन, प्लास्टिक के गिलास, चम्मच एवं थर्मोकॉल आदि के उत्पादों का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर मा0 एन0जी0टी0, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड एवं राज्य सरकार के आदेशों के तहत दंडात्मक कार्यावाही की जायेगी।
23. व्यवसायों के लाईसेंस हेतु ऑन लाइन आवेदन <https://nagarsewa.uk.gov.in/> में माध्यम से किया जा सकता है।

लाईसेन्स गजट 2022-23

क्र०सं०	मद का विवरण	प्रस्तावित दरें वार्षिक
1	बैंकट हॉल/मैरेज हॉल	1500.00
2	होटल लॉजिंग	
	20 बेड तक	1000.00
	20 से 30 बेड तक	1500.00
	30 से अधिक बेड तक	2500.00
3	03 स्टॉर होटल	4000.00
	04 स्टॉर होटल	6000.00
	05 स्टॉर होटल	8000.00
4	रेस्टोरेंट नॉन ए.सी.	250.00
5	रेस्टोरेंट ए.सी.	500.00
6	बियर बार	5000.00
	हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम	
7	हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम/मेटरनिटी होम 1-20 बेड तक	2000.00
8	हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम 21-50 बेड तक	5000.00
9	हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम 51-100 बेड तक	6000.00
10	हॉस्पिटल/ प्रसुति गृह मल्टिस्पेशलिस्ट हॉस्पिटल 101 बेड से उपर	8000.00

11	एक्स-रे सेंटर	500.00
12	पैथोलॉजी सेंटर	1000.00
13	पैथोलॉजी सैम्पल कलैक्शन सेंटर	500.00
14	डाईग्नोस्टिक सेंटर/एक्स-रे अल्ट्रासाउण्ड/सीटी0 स्कैन, पैथोलॉजी सेंटर सहित	2000.00
15	डाईग्नोस्टिक सेंटर/एक्स-रे अल्ट्रासाउण्ड/सीटी0 स्कैन, पैथोलॉजी सेंटर, एम0आर0आई0 सहित	2500.00
16	मेडिकल शॉप/आयुर्वेदिक शॉप/पतंजली स्टोर	250.00
17	डेंटल क्लीनिक	1000.00
18	प्राइवेट क्लीनिक-एलोपैथीक	1000.00
19	यूनानी/आयुर्वेदिक /होम्योपैथिक क्लीनिक	500.00
20	वैटनरी हॉस्पिटल	250.00
21	फिजियोथैरेपी क्लीनिक/योगा केन्द्र	500.00
	परिवहन	
22	ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन के एजेन्सी)	500.00
23	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी वाहन सहित	800.00
24	मिनी बस	500.00
25	ई-रिक्शा	250.00
26	हाथ ठेला	100.00
27	बस (इन्टर सिटी)	250.00
28	ट्राली /पानी टैंकर	200.00
29	अन्य चार पहिया वाहन व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन इंजन चलित	500.00
30	मोटर साइकिल /स्कूटर एजेन्सी सेल्स /सर्विस	1000.00
31	मोटर वाहन एजेन्सी सेल्स अथवा सर्विस (चार पहियों)	2000.00
32	साइकिल की दुकान सेल्स अथवा सर्विस	200.00
33	रिक्शा की दुकान सेल्स अथवा सर्विस	200.00
34	वर्कशॉप /कार, ट्रक, बस, ट्रैक्टर रिपेयर	250.00
35	वर्कशॉप मोटर साइकिल/स्कूटर	200.00
36	ऑटो उपकरण सेल्स	250.00
37	तांगा, बुगी लाइसेन्स	100.00
	पेट्रोलियम	
38	पेट्रोल/डीजल ऑयल कम्पनी	2000.00
39	डीजल-पेट्रोल पम्प फिलिंग स्टेशन	1000.00
40	मोबिल ऑयल आदि फुटकर विक्रेता	200.00
41	केरोसिन, स्प्रीट, एसिड विक्रेता	500.00
42	जनरेटर डीजल व्यवसायिक दुकान	500.00
	अन्य व्यवसाय	
43	मोटर ट्रेनिंग स्कूल	500.00
44	आटा चक्की	250.00
45	आटा मिल/धान मिल	500.00
46	धुलाई गृह/ड्राईक्लीनर/लान्ड्री	250.00
47	कैटरिंग लाइसेन्स	500.00
48	साबुन फैक्ट्री	500.00
49	आइसक्रीम फैक्ट्री, कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर फैक्ट्री	500.00
50	कबाड़ी	250.00
51	चूना भट्टी	200.00
52	जूते, कपड़े, शोरूम ब्रांडेड-	500.00
	जूते, कपड़े, शोरूम नॉन ब्रांडेड-	200.00

53	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेंट, रेत, ईट, पत्थर, मारबल, टाईल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर आदि फुटकर विक्रेता	500.00
54	बिजली का सामान विक्रेता	200.00
55	हेयर कटिंग सैलून	200.00
56	हेयर कटिंग सैलून ए.सी.	300.00
57	स्पा	1000.00
58	ब्यूटी पार्लर	500.00
59	कुकिंग गैस एजेन्सी एलपीजी	500.00
60	जनरल स्टोर	500.00
61	जनरल स्टोर (छोटा)	100.00
62	टेलरिंग शॉप	250.00
63	बुटिक	500.00
64	कोयला थोक विक्रेता	250.00
65	मसाला मिल/पल्स ग्राइण्डर	250.00
66	ज्वेलर्स की दुकान ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड	1500.00 500.00
67	विज्ञापन एजेन्सी / ग्लोसाईन / पलैक्स	500.00
68	डेयरी फार्म / घी एण्ड मिल्क डेयरी	500.00
69	डेयरी फैक्ट्री	25000.00
70	भूसा स्टोर	200.00
71	केबिल / डिश टी0वी0 आपरेटर	1000.00
72	आर्किटेक्ट कन्सल्टेन्ट विधि, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कॉस्ट एकाउन्टेन्ट	1000.00
73	फाईनैन्स कम्पनी चिट फण्ड	2000.00
74	गोदाम	250.00
75	इन्श्योरेंस कम्पनी प्रति शाखा	2000.00
76	आईस फैक्ट्री/कोल्ड ड्रिंक/सोडा वाटर फैक्ट्री/ ड्रिंकिंग वाटर फैक्ट्री	500.00
77	टेन्ट हाउस	500.00
78	न्यूज पेपर विक्रेता	200.00
79	फर्टीलाइजर शॉप/बीज भण्डार/खाद विक्रेता/कृषि दवाई	200.00
80	मिठाई की दुकान	200.00
81	मिठाई की दुकान ए.सी. रेस्ट्रॉ के साथ	500.00
82	सब्जी/फल की दुकान	250.00
83	सब्जी / फल की आढ़त	300.00
84	देशी शराब की दुकान	8000.00
85	अंग्रेजी शराब की दुकान	12000.00
86	शराब गोदाम (देशी/अंग्रेजी)	5000.00
87	भैंसा मांस की दुकान बकरा मांस की दुकान सुअर मांस की दुकान	500.00 500.00 500.00
88	मुर्गा मांस/अण्डा विक्रेता की दुकान	500.00
89	मछली विक्रेता/झिंगा विक्रेता	500.00
90	फर्नीचर का शोरूम	500.00
91	फर्नीचर की दुकान	300.00
92	मेला-प्रदर्शनी-अस्थायी बाजार प्रतिमाह शुल्क	1000.00
93	लाइट / साउण्ड डी0जे0 की दुकानें	500.00

94	एम्पलीफायर वाहन द्वारा लाउडस्पीकर प्रचार/ साईकिल / दोपहिया पर लाउड स्पीकर से प्रचार-प्रसार। रिक्शा पर लाउड स्पीकर से प्रचार-प्रसार। टुक-टुक / तिपहिया वाहन से प्रचार-प्रसार। फोर व्हीलर से प्रचार-प्रसार। फोर व्हीलर पर एल0ई0डी0 के माध्यम से प्रचार-प्रसार।	25.00 प्रतिदिन 50.00 प्रतिदिन 250.00 प्रतिदिन 500.00 प्रतिदिन 500.00 प्रतिदिन
95	बैण्ड मास्टर की दुकान	500.00
96	फोटो स्टूडियो/विडियो फिल्म मेकर/साईबर कैफे/विडियो गेम पॉलर /सी0डी0, डी0वी0डी0 शॉप	500.00
97	प्रिंटिंग प्रेस	500.00
98	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र फ्रैन्चाईजी प्राप्त अन्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (व्यक्तिगत)	1000.00 250.00
99	कम्प्यूटर शॉप/हार्डवेयर साफ्टवेयर	250.00
100	कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड फ्रैन्चाईजी प्राप्त कोचिंग सेंटर रजिस्टर्ड (व्यक्तिगत)	1000.00 500.00
101	मोबाईल टॉवर प्रति	5000.00
102	लोहार	100.00
103	पोल्ट्री फार्म	500.00
104	धर्मकांटा	500.00
105	मेला एवं प्रदर्शनी हेतु अस्थाई लाईसेंस (नगर पंचायत लालकुआँ के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली भूमि पर)	1.00 रु0 प्रति वर्ग मी0 प्रतिदिन
106	व्यायामशाला/जिम/हेल्थ रिसोर्ट (इन्डोर)	500.00
107	प्रोपर्टी डीलर	500.00
108	प्राइवेट स्कूल कक्षा 5 तक (प्राइमरी)	500.00
109	प्राइवेट स्कूल कक्षा 8 तक (जूनियर हाईस्कूल)	800.00
110	प्राइवेट स्कूल कक्षा 10 तक (हाईस्कूल)	1000.00
111	प्राइवेट स्कूल कक्षा 12 तक (इण्टरमीडियट)	1500.00
112	चाय की दुकान/जूस स्टॉल/पान खोखे, फड़	200.00
113	कोटन मशीन	100.00
114	शुगरकेन जूस	100.00
115	फेबरीकेटर्स इन्जीनियरस/वैल्विंग मशीन	500.00
116	कम्प्रेसर पंचर संबंधी	100.00
117	होस्टल /पेइंग गेस्ट 1 से 20 बेड तक 20 से 40 बेड तक 40 से अधिक	1000.00 2000.00 3000.00
118	ढाबा भोजनालय	500.00
119	टेला व्यवसायी	100.00
120	लकड़ी टॉल	500.00
121	आरा मशीन	500.00
122	खराद मशीन/दाब मशीन/बरमा मशीन	500.00
123	डेटिंग पेटिंग वर्क शाप	500.00
124	एक्सपेर /पिराई मशीन	700.00
125	वाहनों की धुलाई	500.00
126	बैंक ए0टी0एम0 सहित	3000.00
127	बैंक	2000.00

128	ए0टी0एम0	1000.00
129	बिल्डर्स/रजिस्टर्ड	500.00
130	ठेला स्वीट्स, आईसक्रीम व फूड आइटम	200.00
131	बिस्कुट बेकरी	200.00
132	कन्फेक्शनरी	500.00
133	बुक डिपों / पब्लिशर / स्टेशनरी आपूर्तिकर्ता	500.00
134	अनाज, तिलहन, चीनी-गुड़, खांडसारी विक्रेता	500.00
135	चूड़ी विक्रेता	200.00
136	टेलीविजन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वांशिग मशीन व अन्य इलैक्ट्रानिकएप्पलाइसेंस शोरूम	500.00
137	वॉचक्लॉक रिपेयर/सेलर	200.00
138	मोबाईल फोन आउटलेट	500.00
139	सुपर मार्केट / मेगा मार्ट	5000.00
140	शॉपिंग मॉल / कॉम्प्लेक्स	2000.00
141	सिनेमा हॉल	500.00
142	सिनेमा हॉल प्रति शो	50.00
143	मल्टीप्लेक्स	1000.00
144	पौधों की नर्सरी	500.00
145	फैक्ट्री लघु - मध्य - दीर्घ -	2000.00 3000.00 5000.00
146	गैस पाईपलाइन एजेन्सी	10000.00
147	ब्लड बैंक	3000.00
148	तांगा/बुग्गी	250.00
149	उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय	500.00

दण्ड

नगर पंचायत सीमान्तर्गत तैयार की गयी उपरोक्त उपविधियों के किसी भाग/अंश का उल्लंघन होने पर प्रथम बार में लाईसेन्स शुल्क की 10 प्रतिशत धनराशि या न्यूनतम रू0 50.00 व अधिकतम रू0 1000.00 अर्धदण्ड देय होगा एवं द्वितीय बार उल्लंघन पर लाईसेन्स शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि या न्यूनतम रू0 100.00 व अधिकतम रू0 2000.00 अर्धदण्ड देय होगा तथा तीसरी बार लाईसेन्स शुल्क की 30 प्रतिशत धनराशि या न्यूनतम रू0 200.00 व अधिकतम रू0 3000.00 अर्धदण्ड देय होगा। पुनः उल्लंघन किये जाने पर लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। अर्धदण्ड की वसूली भू-राजस्व के भांति की जा सकेगी।

पूजा,
अधिशायी अधिकारी,
नगर पंचायत लालकुआँ
जिला-नैनीताल।

लालचन्द्र सिंह,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत लालकुआँ
जिला-नैनीताल।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, नैनीताल

उपविधि सूचना

07 जनवरी, 2023 ई0

पत्रांक 1810/XV-18—नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298(झ)घ एवं भारत का राजपत्र नई दिल्ली दि0 25/09/2000 के नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ङ), 15(च) एवं 15(यच) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन और हथालन नियम हेतु नगर पालिका परिषद् नैनीताल द्वारा नगरीय ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए अपने क्षेत्राधिकार में डोर-टू-डोर कलेक्शन लागू किये जाने हेतु निम्नलिखित उपविधियाँ बनाई गयी हैं। जो सूचनार्थ प्रकाशित हैं।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख

(1) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद् नैनीताल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2021 कहलायेंगे।

(2) ये उप-नियम नगर पालिका परिषद् नैनीताल के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. ये उप-नियम नगर पालिका परिषद् नैनीताल की सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं

(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस उप नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू हैं:-

(a) "बल्क उद्यान और बागवान कचरा" का अर्थ हैं, उद्यानो, बागो आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ों की छटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ों की कटिंग, टहनियां, लकड़ी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेड़ों की छटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता हैं।

(b) "बल्क कचरा उत्सर्जन का अर्थ हैं कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहा एस. डब्ल्यू.एम नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;

(c) "संग्रह" का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुंचाना;

(d) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ हैं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् नैनीताल, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।

(e) "निर्माण एवं विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया हैं।

(f) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्तर्गत किया जाना हैं।

(g) "सामुदायिक कूड़ा घर (ढलाव)" का अर्थ है, नगर पालिका द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सड़क किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा समक्ष अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;

- (h) "कंटेनराइज्ड हैड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर पालिका या उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;
- (i) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को नगर निगम के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए नगर पालिका द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे नगर पालिका या नगर पालिका द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना;
- (j) "ई-कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई-कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया है;
- (k) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)" का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैक्ट करने के लिए किया गया है और प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती है, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;
- (l) "कूड़ा-कचरा" का अर्थ है, सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल जिसे फेंकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचाने की आशंका हो।
- (m) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्संबंधी अनुमति देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।
- (n) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है;
- (o) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है।
- (p) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकड़े होते हैं; और उनके ईंधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें रिफ्यूज डेराइब्ड ईंधन कहा जाता है।
- (q) "निर्धारित" का अर्थ है, एसडब्ल्यूएम नियमों और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित;
- (r) "सार्वजनिक स्थल" का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ है, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं;
- (s) "संग्रहण" का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;
- (t) "सैनेटरी वर्कर" का अर्थ है, नगर पालिका के इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिये नगर पालिका /एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;
- (u) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;
- (v) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभारी" का अर्थ है, नगर पालिका द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कचरा उत्सर्जक प00र लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें;
- (w) "खाली प्लॉट" का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थल, जिस पर किसी का कब्जा न हो;

(4) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत होगा।

अध्याय-2

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

* ठोस कचरे का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क:-

- (1) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 में निर्दिष्ट हैं।
 - (2) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर पालिका परिषद्, नैनीताल के अधिशासी अधिकारी/ नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
 - (3) नगर पालिका परिषद्, नैनीताल ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।
 - (4) इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।
 - (5) वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बाजूए 11 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छह महीने के बजाये साढ़े पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।
 - (6) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती 3 वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
 - (7) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान/ व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
 - (8) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।
09. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड :- (क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
- (a) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।
 - (b) जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, नैनीताल, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अधिशासी अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक कर अधीक्षक, कर निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चौकी, थाना प्रभारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दंड राशि अनुसूची 2 में दी गई है।
 - (c) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 2 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
 - (d) निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

विविध

10. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे अध्यक्ष/ बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।
11. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : नगर पालिका परिषद्, नैनीताल अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, ताकि इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र यानियंत्रण में आने वाले इलाकों सुनिश्चित किया जा सके। कोई कठिनाई होने की स्थिति में उत्तराखण्ड सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।
12. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप-नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1

ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र स	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (यूजर चार्ज रुपये में)
1	प्रति परिवार सामान्य	रु0 60.00
2	गरीबी रेखा से नीचे घर (मलिन बस्ती, बी0पी0एल0)	रु0 20.00
3	ढाबा	रु0 110.00
4	रैस्टोरेन्ट	रु0 330.00
5	पान स्टॉल/टी स्टॉल/ठेले	रु0 60.00
6	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस 20 कमरों तक	रु0 2000.00
7	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस 20 कमरों से 50 कमरों तक संख्यानुसार प्रति कमरा दर रु100/-	रु0 5000.00
	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस 50 कमरों से 100 कमरों तक संख्यानुसार प्रति कमरा दर रु100/-	रु0 10000.00
8	घर्मशाला	रु0 200.00
9	कार्यालय 50 कर्मचारियों तक	रु0 330.00
10	कार्यालय 100 कर्मचारियों तक	रु0 550.00
	कार्यालय 300 कर्मचारियों तक	रु0 1100.00
	कार्यालय 300 कर्मचारियों से अधिक	रु0 1350.00
11	फैक्ट्री	रु0 1200.00
12	लघु उद्योग	रु0 350.00
13	वर्कशाप	रु0 250.00
14	दुकान	रु0 110.00
15	सिनेमा हॉल	रु0 600.00
16	ब्रेकरी/फूड ज्वाइन्ट ब्रेकरी आउटलेट	रु0 550.00
17	हॉस्टल 1 से 10 कमरों तक	रु0 500.00
18	हॉस्टल 10 कमरों से अधिक	रु0 850.00
19	बैंक	रु0 550.00
20	फास्ट फूड	रु0 330.00
21	स्वीट शाप	रु0 330.00
22	वेजीटेबिल/फल, शब्जी की दुकान	रु0 70.00
23	समस्त सरकारी स्कूल	रु0 100.00

1	2	3
24	निजीस्कूल कक्षा 1 से 8 तक	रु0 600.00
25	निजी स्कूल इण्टरमीडिएट तक	रु0 1200.00
26	निजी स्कूल कक्षा 1 से 12 तक (मय बोर्डिंग) छात्र/छात्रायें संख्या 01 से 500 तक	रु0 2000.00
27	निजी स्कूल कक्षा 1 से 12 तक (मय बोर्डिंग) छात्र/छात्रायें संख्या 501 से 1000 तक	रु0 5000.00
28	निजी स्कूल कक्षा 1 से 12 तक (मय बोर्डिंग) छात्र/छात्रायें संख्या 1000 से अधिक	रु0 10000.00
29	बैकटहॉल/बरातघर	रु0 1100.00
30	मांस एवं मछली	रु0 550.00
31	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम 20 बेड तक (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	रु0 1000.00
32	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम 21 से 40 बेड तक (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	रु0 1500.00
33	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम 41 से 100 बेड तक (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	रु0 2750.00
34	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम 100 बेड अधिक (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	रु0 5500.00
35	क्लीनिक/डेंटल क्लीनिक फिजियोथिरोपी/डायगनोस्टिक सैन्टर (जैसे एक्स-रे, सी.टी.स्केन अल्ट्रासाउण्ड, पैथोलौजी आदि)	रु0 550.00
36	चाय की दुकान	रु0 50.00
37	कबाड़ी की दुकान	रु0 400.00
38	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी आदि आयोजन जिनसे अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु0 0.10/प्रति स्कवायर फिट प्रतिदिन/500/-रु0 प्रतिदिन जो अधिक हो
39	ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 0.50घन मी0 तक	रु0 350.00
40	ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 3.0 घन मी0 तक	रु0 700.00
41	ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 6.0 घन मी0 तक	रु0 1550.00
42	ढहान और निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट 6.0 घन मी0 अधिक पर	रु0 2700.00
43	गन्ने रस/अन्य जूश विक्रेता	रु0 120.00 प्रतिमाह
44	उपरोक्त मदों के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय हेतु ।	रु0 500.00

इस्तेमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज)/प्रभार का भुगतान नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा अधिकृत संस्था/कम्पनी द्वारा मांग जारी होने के 30 दिनों के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज)/प्रभार पर 10% (प्रतिशत) की दर से नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा या नगर पालिका परिषद्, नैनीताल द्वारा अधिकृत संस्था/कम्पनी या अनुभाग द्वारा विलम्ब भुगतान/प्रभार लगाया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज)/प्रभार का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं से बकाये शुल्क की वसूली भू-राजस्व की भाँति की जायेगी।

अनुसूची-2
जुर्माना/दंड

क्र स	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	कचरे को पृथक् करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	आवासीय	100
			बल्क जन्रेटर	500
			5000 वर्ग मीटर से कमक्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल पार्टी लान प्रदर्शनी और मेले स्थल	10000
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लब सिनेमाघर पब्स सामुदायिक हॉल, मल्टीप्लेक्सेज और अन्य	5000
			ऐसे स्थान 5000मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	500
			फिस,मीट विक्रेता द्वारा कूड़े को पृथक्करण तरीके से न रखना	800
2	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	1 सडक/गली में कूड़ा फैकना,थूकना	उल्धनकर्ता	200 से 5000एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूड़ा फैकना, एवं थूकनाप्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।
		2.नहाना,पैशाब करना जनवरो को चारा खिलाना, कपडे धोना वाहन धोना,गोबर नाली में बहाना		500
2	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ)	नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना। नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	100
			गैर-आवासीय/बल्क जन्रेटर	500
3	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना।	आवासीय	500
			गैर-आवासीय/बल्क जन्रेटर	5000

4	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2),15(ट),	ठोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000 से 20000
5	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या योजना सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000
6	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूड़ादान न रखने एवं कूड़े को पृथक्करण न करने,अपशिष्ट भण्डारन डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	200
7.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2) 15(छ)	सार्वजनिक स्थलों सड़कों गलियों आदि में गंदगी फैलाना/कुत्ते/अन्य जानवरों द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित कचरे के निपटान में विफलता	अपराधी	500

निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा				
8.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार कचरे के निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन, आर. डब्ल्यू.ए	5000
			बजार एसोसिएशन,संघ	10,000
9.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	5000
			संस्थान	10000
10.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार कचरे का निपटान में विफलता	होटल	10000
			रेस्टोरेंट	5000
11.	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(2)	उत्पादन के कारण सृजित पैकेजिंग कचरेको वापस लेने की प्रणाली कायम किये बिना डिस्पोजल उत्पादों की बिक्री अथवा विपणन	विनिर्माता और/या ब्रॉड ऑनर/स्वामी	50000
12	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 17(3)	नियमों के अनुसार उपाय करने में विफलता	विनिर्माता और ब्रॉड स्वामी और विपणन कंपनिया	25000

13	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15(ड)	नियमों के उपाय करने भवन योजना में अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र स्थापित करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता, ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी या मॉकर्ट काम्पलेक्स आदि	25000
14	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(ग)	गलियो पहाडियो सार्वजनिक स्थलो म अपशिष्ट यथा कागज, पानी की बोतल, शराब की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक कैन, टैट्टा पैक अन्य कोई प्लास्टिक या कागज अपशिष्ट का फेंकने पर	उल्लंघनकर्ता/पर्यटक/वाहन/चालक	500
15	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 20(घ)	नगर पालिका परिषद्, नैनीताल की उप विधि का होटल/अतिथिग्रह में बोर्ड लगाकर व्यवस्था करने में विफलता	उल्लंघनकर्ता/होटल/अतिथिग्रह स्वामी	500
16		सार्वजनिक सभाओं जलूस प्रदर्शिनियों, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलिया, वाणिज्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शन आदि सहित से सार्वजनिक स्थलो पर आयोजित गतिधियों के क्षेत्र एवं आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करने में विफलता)	आयोजनकर्ता	5000

ह० (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्, नैनीताल।

ह० (अस्पष्ट),
अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, नैनीताल।